

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 834 राँची, गुरुवार

5 अग्रहायण, 1937 (श॰)

26 नवम्बर, 2015 (ई॰)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

संकल्प

26 नवम्बर, 2015

विषयः-

The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 ਰਥਾ The Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 के तहत कोल मंत्रालय, भारत निर्गत सफल डाकवक्ता (Successful Bidder) सरकार द्वारा Vesting/Allotment Order के आलोक में Coal Mines (S.P.) Act, 2015 अंतर्गत पूर्व आवंटी के स्वामित्व की विवाद-रहित अर्जित रैयती भूमि एवं निजी से क्रय की गयी विवाद रहित भूमि को वर्तमान दर के आधार पर भूमि के रजिस्ट्रेशन एवं मुद्रांक शुल्क की अदायगी पर सफल डाकवक्ता (Successful Bidder) के पक्ष में हस्तांतरण/म्यूटेशन करने एवं भूमि के अंतरण/हस्तांतरण हेतु संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता/भूमि सुधार उप समाहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को शक्ति प्रत्यायोजित करने तथा लीज/बंदोबस्त सरकारी भूमि को हस्तांतरित करने के संबंध में।

संख्या-4/स.भू.(कोल ब्लाक)-75/15-5281/रा0,--भारत सरकार द्वारा The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 तथा The Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा W.P(Crl) No.-120/2012 में पारित न्यायादेश दिनांक 24 सितम्बर, 2014 द्वारा रद्द कोल ब्लोक्स की नीलामी/आवंटन की गई है।

- 2. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अर्द्धसरकारी पत्रांक- 13016/36/2015-CA-111, दिनांक-27.07.2015 के द्वारा Coal Mines (SP) Act, 2015 के अंतर्गत भूमि का नामांतरण/हस्तांतरण का कार्य सफल डाकवक्ता (Successful Bidder) के पक्ष में पूर्व आवंटियों के द्वारा किये जाने के संबंध में स्पष्टतः उल्लेखित किया गया है कि "The land transfer and mutation may be done on the basis of Vesting/Allotment order in accordance with the provisions of the Coal Mines (SP) Act, 2015."।
- 3. कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक-F.No.-13016/36/2015-CA-III, दिनांक-13.10.2015 के द्वारा The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 के आधार पर कोल ब्लोक्स/माईन्स में निहित भूमि के हस्तांतरण/दाखिल खारिज के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 के आधार पर Vesting/Allotment Order के द्वारा पूर्व आवंटी के स्वामित्व की भूमि सफल डाकवक्ता के पक्ष में भूमि पर उपलब्ध सभी संसाधनों के साथ सीधे बिना किसी अवरोध के निहित कर दी गई है एवं उक्त निहित भूमि के Successful Bidder के पक्ष में हस्तांतरण/म्यूटेशन की प्रक्रिया हेतु केवल मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क लिये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में उल्लेखित किया गया है कि "That the Act provides for vesting of land of the prior allottee in favour of successful allottee by way of Vesting/Allotment Order which contains the relevant details of such vested land. However, such vesting of land is required to be recorded/mutated under the provisions of the relevant statute. Also, stamp duty is applicable for such recording/mutation."
- 4. प्राप्त पत्र के द्वारा सफल डाकवक्ता के पक्ष में भूमि हस्तांतरण करने के लिये भूमि के नये दर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया के संदर्भ में उल्लेखित किया गया है कि "Thus, State Government's guidelines which stipulate payment of sum to the Government on the basis of assessment of present value of land are not applicable in the cases of vesting done under the said Act, it is also pertinent to mention that the special Act has an overriding effect on any other law inconsistent with it and therefore, the provisions of the Act will prevail over any rule or guideline which provides for revaluation of land."
- 5. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि:-

- (i) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश से आच्छादित प्रस्तुत मामले में The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 तथा The Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 के तहत कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सफल डाकवक्ता (Successful Bidder) को निर्गत Vesting/Allotment Order के आलोक में The Coal Mines (S.P.) Act, 2015 अंतर्गत पूर्व आवंटी के स्वामित्व की विवाद-रहित अर्जित रैयती भूमि एवं निजी वार्ता से क्रय की गयी विवाद रहित भूमि को वर्तमान दर के आधार पर भूमि के रिजस्ट्रेशन एवं मुद्रांक शुल्क की अदायगी पर Successful Bidder के पक्ष में हस्तांतरण/म्यूटेशन करने एवं भूमि के अंतरण/हस्तांतरण हेतु संबंधित जिले के अपर समहर्ता/भूमि सुधार उप समहर्ता/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को प्राधिकृत करने के लिए संबंधित उपायुक्त को शिक्त प्रदान की जाती है।
- (ii) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश से आच्छादित प्रस्तुत मामले में The Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 तथा The Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014 के तहत कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सफल डाकवका (Successful Bidder) को निर्गत Vesting/Allotment Order के आलोक में Coal Mines (S.P.) Act, 2015 अंतर्गत पूर्व आवंटी को लीज/बंदोबस्त सरकारी भूमि को राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा. दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 की कंडिका-4(I) को शिथिल करते हुए वर्तमान आवंटी को हस्तांतरित की जाती है।
- (iii) नये Coal Block आवंटी को सरकारी भूमि का लीज हस्तांतरण हेतु पूर्व निर्धारित सूचकांक के अनुसार पूर्व आवंटी के द्वारा भुगतान की गई अवधि के पश्चात् लीज की शेष अवधि के लिए नये आवंटी के द्वारा पूर्व की गणना के अनुसार देय वार्षिक व्यवसायिक लीज रेन्ट तथा सेस का भुगतान करना होगा।
- 6. उक्त निर्णय में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-24 नवम्बर, 15 को मद संख्या-20 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, रेमण्ड केरकेट्टा, सरकार के अपर सचिव ।
